## भारतीय बैंकिंग व्यवस्था

- भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की नीव ईस्ट इंडिया कम्पनी मेने डाली क्योंकि इससे पूर्व बैंकिंग का कार्य प्राय: महाजनों एवं साहूकारों द्वारा सम्पन्न किया जाता है |
- 18वी शताब्दी में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने मुम्बई तथा कोलकाता में कुछ 'एजेंसी गृहों' की स्थापना की थी,जो आधुनिक बैंकों की भांति कार्य करते थे |
- भारत में आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ 'The General Bank of India' से हुआ जिसकी स्थापना 1786 में हुई | यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम मिश्रित पूँजी बैंक विदेशी पद्धति के सहयोग से एलेक्जेंडर एवं कम्पनी 'बैंक ऑफ हिन्दुस्तान'के नाम से 1790 में कोलकाता में स्थापित किया गया था | लेकिन ये दोनों बैंक जल्द ही असफल हो गए |
- भारत में समिति दायित्व के आधार पर भारतीयों द्वारा संचालित सबसे पहला व्यवसायिक बैंक 'अवध कॉमर्शियल बैंक'जो 1881 में स्थापित किया गया जबकि पूर्णतया भारतीयों द्वारा संचालित सबसे पहला भारतीय बैंक 1894 में स्थापित 'पंजाब नेशनल बैंक' था |
- बैंकिंग व्यवसाय से जुडी कोई भी कम्पनी जिसकी प्रदत्त पूँजी तथा संचित कोष 5 लाख रुपयों से अधिक हो,रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में शामिल कर लि जाती है | जो अनुसूचित बैंक कहलाती है |

### स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का विकास :

- निजी अंशधारियों द्वारा तीन प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना क्रमश: 1806 माँ बैंक ऑफ़ बैंक बंगाल,1840 में बैंक ऑफ़ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक मद्रास के नाम से की गई | 1921 में इन तीनों बैंकों को संयुक्त करके 'इम्पिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया' की स्थापना की गई और गोरवाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर 1 जुलाई,1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम बदल कर 'स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया' रख दिया गया |
- 1906 के बाद बैंकिंग का देश में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ देश के तत्कालीन चार बड़े बैंक इस प्रकार थे-
- Bank of India -1906
- Bank of Baroda-1908
- Central Bank of India-1911
- Bank of Mysore-1913
- 1917 से 1923 का समय बैंकिंग संकट का समय माना जाता है | SBI-का मुख्यालय मुम्बई में है |
- 1957 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का दर्जा दिया गया | बाद में स्टेट बैंक ऑफ़ जयपुर औए स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर को मिला दिया गया | 1959 में SBI के 7 सहायक बैंक थे-1.स्टेट बैंक ऑफ़ जयपुर एवं बीकानेर, 2.स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला,3.स्टेट बैंक ऑफ़ इन्दौर 4.स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र,4.स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद,5.स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर तथा 7.स्टेट बैंक ऑफ़ टावनकोर | वर्तमान में SBI के 5 सहायक बैंक है |
- नोट:7 बैंकों में से स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र, का जुलाई 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ़ इन्दौर का जून 2009 में SBI में विलय करने के निर्णय के फलस्वरूप SBI समूह में पाँच बैंक है |
- 19 जुलाई,1969 में श्री मती इंदिरा गाँधी की सरकार के समय 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया जिनके पास 50 करोड़ रूपये या उससे आधिक राशि जमा थी | 15 अप्रैल,1980 में उन 6 वाणिज्यिक बैंकों की राष्ट्रीयकृत किया गया जिनके पास 200 करोड़ रूपये या इससे अधिक राशि जमा थी |
- **राष्ट्रीयकरण:** इसके उन्तर्गत सरकार गरीब लोगों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनती है जैसे-बैंक ऑफ़ इंडिया,PNB आदि |
- इस प्रकार देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14+6=20 थी परन्तु सरकार द्वारा 4 दिसम्बर,1993 को NEW Bank of India का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया | अब देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घट कर 19 रह गई |
- भारत का पहला बैंक 'यूनाइटेड बैंक' जिसका विनिवेश किया गया |

- ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स भारत का एकमात्र ऐसा बैंक है जिसमें सरकार की भागीदारी 100% है |
- वर्तमान में 26-सार्वजनिक बैंक,19-राष्ट्रीयकृत बैंक,1-(IDBI) और 6 SBI और इसके 5 सहायक बैंक है SBI-अंशत:राष्ट्रीयकृत बैंक है |
- भारतीय स्टेट बैंक वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है |

    - भारतीय रिजर्व बैंक का विकास :

- 1926 में गठित हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों पर 'रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम,1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल,1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई |
- 1 जनवरी,1949 का उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया | तथा मार्च 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों को नियन्त्रण रखने का विस्तृत अधिकार प्राप्त ही गया |
- RBI का सामान्य प्रबंध और संचलन एक 20 सदस्यीय केन्द्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है केन्द्रीय निदेशक मंडल में एक गर्वनर,4 उपगर्वनर,एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी,भारत सरकार द्वारा मनोनीत 10 ऐसे निदेशक,जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलूओं का प्रतिनिधित्व करते है तथा केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 4 ऐसे निदेशक,जो स्थानीय बोड़ो का प्रतिनिधित्व करते है,होते है |
- RBI का मुख्यालय मुम्बई में स्थित है केन्द्रीय बोर्ड के चरों स्थानीय बोर्ड जिनके मुख्य कार्यालय-मुंबई,कोलकाता,चेन्नई और नई दिल्ली में है |
- RBI के प्रचलन तथा बैंकिंग विभाग मुंबई,कोलकाता,जयपुर,चेन्नई,नई दिल्ली,बायखला,बंगलौर,नागपुर तथा कानपूर में स्थित है | इसका एक कार्यालय लंदन में भी है |

## RBI का कार्य :

- करेसी नोटों का निर्गमन करना | करेंसी नोटों के निर्गमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक अलग नोट निर्गमन विभाग है |
- देश की साख तथा बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण रखना |
- RBI केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बैकर एजेंट तथा आर्थिक एवं वित्तीय मामलों पर परामर्श दाता के रूप में कार्य करता है |
- 1 रूपये के नोट तथा सिक्कों की निर्गमन भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है जबकि अन्य सभी नोटों पर RBI के गर्वनर के हस्ताक्षर होते है |
- विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सबसे पहले 1790 में फ्रांस में अपनाई गई थी |
- सिक्कों तथा पदकों की ढलाई के लिए देश में चार प्रमुख टकसालें है-1.मुंबई (1830 में स्थापित),2.कोलकाता(1950 में स्थापित),3.हैदराबाद(1903 में स्थापित),4.नोएडा(1989 में स्थापित) |
- विदेशी मुद्रा को आरक्षित तथा विदेशी मुद्रा की विनियम दर को केवल RBI निर्धारित करता है |
- **न्यूनतम आरक्षित प्रणाली** के अनुसार RBI अधिनियम 1957 के आधार पर RBI करेसी लागू करता है | प्रारंभ में यह आरक्षित करेंसी 200 करोड़ थी -115 करोड़ स्वर्ण तथा 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में |
- RBI मुख्यत:IMF का वैकल्पिक गर्वनर होता है |
- RBI ही मौद्रिक नीति जारी करता है मौद्रिक नीति के माध्यम से RBI बाजार में साख का विनियमन अर्थात् मुद्रास्फीति की नियन्त्रिण करता है अर्थात् बाजार में तरलता की अधिकता को कम करना तथा कमी को अधिक करना आदि के लिए उपाय अपनाना |
- RBI के वर्तमान गर्वनर डी.सुब्बाराव है | तथा 4 उपगर्वनर-डॉ.के.सी.चक्रवती,2.डॉ.सुबीर गोकरण,3.श्री आनन्द सिन्हा,4.श्रीहरुन रशिद खान |

    - RBI के अतिरिक्त भारतीय सार्वजनिक बैंक :

- IDBI-भारतीय औद्योगिक विकास बैंक -1964 में स्थापित हुआ | औद्योगिक क्षेत्र में सुप्रीम बैंक है | इसका मुख्यालय मुंबई में है
- NABARD-आग वर्णित है
- SBI-स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया,1955 में स्थापित | उपभोक्ता बाजार का सुप्रीम बैंक | इसका मुख्यालय मुंबई में है

- SIDBI-Small Scale Industries Development Bank Of India (लघु स्तरीय औद्योगिक विकास बैंक ) 1990 में स्थापित | लघु उद्योगों के लिए सुप्रीम बैंक | इसका मुख्य बैंक लखनऊ में है |
- EXIM BanK( Export Import Bank)-जनवरी 1982 में स्थपित | आयात-निर्यात के लिए सुप्रीम बैंक | इसका मुख्यालय मुंबई में है |

## बैंक दर :

- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ऐक्ट के अनुसार बैंक दर वह है जिस पर रिजर्व बैंक बिल ऑफ़ एक्सचेज या अन्य व्यापारिक प्रपत्रों को जिन्हें ऐक्ट के अंतर्गत क्रय योग्य ठहराया जाता है | दीर्घवधि ऋण उधर देता है |
- नीची ब्याज दर पर अर्थव्यवस्था में बैंक द्वारा साख सृजन अधिक होगा या निवेश प्रोत्सहित होगा जबकि ऊंची ब्याज दर पर बैंक द्वारा साख सृजन या निवेश हतोत्साहित होगा |
- जब मुद्रा की अत्यधिक वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति की स्थिति हो तो रिजर्व बैंक दर को ऊँची करेगा |
- वर्तमान में बैंक द्वारा 9% है |

## रेपो तथा रिवर्स रेपो :

- सामान्यत : रेपो प्रतिभूतियों का विक्रय उनके पुन: क्रय की क्रिया तथा उल्टा रेपो प्रतिभूतियों का क्रय उनके पुन: विक्रय की क्रिया को प्रदर्शित करता है |
- इसका प्रयोग बैंकों के अलग-अलग दृष्टिकोण से किया जाता है |
- अर्थात् रेपो एक सुविधा है जिसे RBI व्यापारिक बैंकों को प्रदान करता है जिसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते है |
- वर्तमान में रेपो दर 8% है |
- रिवर्स रेपो दर : बैंकों द्वारा RBI के पास अल्पकालीन ऋण (7-14 दिन) जमा पर मिलने वाला ब्याज दर है वर्तमान में RBR-7% है |

  नोट:रेपो दर रिवर्स दर से 1% अधिक होती है |

- 3 मई,2011 को घोषित वर्ष 2011-12 की मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि अब से केवल एक ही नीति दर होगी और वह है रेपो दर |

## MSF(Marginal Standing Facility) :

- मई 2011 में नए उपकरण के रूप में शुरू की गई | वह RBI द्वारा बैंकों को दिए गए अल्पकालीन रातभर ऋण दर लगाने वाला ब्याज दर है |
- वर्तमान में यह 9% है |

## खुले बाजार :

- RBI के द्वारा सरकार के ओर से टेजरी बिल्स एवं अन्य वित्तीय दस्तावेजों को बैंकों एवं आम आदमी के लिए जारी किया जाता है जैसे-AAI - एयरपोर्ट के लिए,NHI-सड़क के लिए |
- इसके बेचने से बाजार में साख की कमी तथा खरीदने से बाजार साख की अधिकता होती है |

## नकद आरक्षण अनुपात :

- रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1) के तहत किए गए प्रावधान के तहत अनुसूचित बैंकों को अपने जमाओं का कुछ निश्चित भाग रिजर्व बकों के पास नकद रूप में जमा रखना अनिवार्य किया गया है बैंकों को अधिक राशि रिजर्व बैंक के पास आरक्षित रखनी होती है जिससे उनके पास तरलता में कमी हो जाती है जिसके चलते उनकी ऋण प्रदान करने की क्षमता भी कम हो जाती है |
- वर्ष 1956 तक,रिजर्व बैंक के पास 1956तक बैंकों के नकद कोष अनुपात के CRR में परिवर्तन कर सकने का अधिकार नही था |
- साख नियन्त्रण के लिए रिजर्व बैंक ने इस अधिकार का प्रयोग पहली बार प्रयोग 1960 में किया | CRR वह अनुपात है जो प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा में से RBI के पास नकद के रूप में जमा करना होता है |
- यह 3-15 तक होता है लेकिन हाल ही मे 3% की न्यूनतम सीमा को समाप्त करके इसे 0-15% के बीच अनुपात किया गया है
- वर्तमान मे CRR-4.75% है ।

- CRR के कम होने पर साख बढ़ता है तथा अधिक होने पर साख कम हो जाता है

## सांविधिक तरलता अनुपात :

- बैकों को अपनी माँग एवं सावधि जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग नकद,स्वर्ण व मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप मे सदा अपने रखना आवश्यक होता है,ताकि जमाकर्ताओं की धन निकासी की जरूरतों को पूरा किया जा सकें,यह अनुपात सांविधिक तरलता अनुपात अर्थात् वह अनुपात जो प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा में से अपने पास रखने होते है
- इसे स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप मे रखा जाता है,SLR को प्रतिभूति,स्वर्ण मे नकद के रूप मे रखा जाता है ।
- यह 25-40 % के बीच थी लेकिन हाल ही मे न्यूनतम सीमा को हटा कर इसे 0-40% कर दिया गया है
- वर्तमान मे SLR 24% है ।
- रिजर्व बैक द्वारा वर्ष 1960 मे पहली बार न्यूनतम नकद कोष अनुपात में परिवर्तन दवारा व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया था,किन्तु सफलता नहीं मिली थी |
- **निजी बैंक :** RBI ACT के तहत निजी क्षेत्र में भी बैंकों को खोलने की अनुमति दी गई है वर्तमान में 35 से अधिक निजी क्षेत्र के बैंक कार्यरत है | निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 74% निर्धारित है | कोटक महिद्रा एवं YES बैंक दो नये निजी क्षेत्र के बैंक है | पहले से कार्यरत कुछ प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में :
    - ICICI बैंक-मुख्यालय-बडौदा
    - AXIS बैंक -मुख्यालय-अहमदाबाद
    - GOLBAL Trust bank - मुख्यालय-सिकंदराबाद
    - TIMES Bank-फरीदाबाद
    - Centurian बैंक-पणजी(गोवा)
    - bank of PUNJAB - चंडीगढ़
    - HDFC Bank- मुंबई
    - IDBI-इंदौर
- प्राथमिक सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में 10 या उससे अधिक लोगों द्वारा मिलकर बनाया जाता है | यह जिला सहकारी संस्था का सदस्य होता है |
- जिला सहकारी संस्था की केन्द्रीय भूमिका होती है व्यक्तिगत सदस्य,प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के सदस्य होते है |राज्य सहकारी से यह दीर्घकालिक कर्ज प्राप्त करते है |
- राज्य सहकारी बैंक की सर्वाच्च भूमिका होती है राज्य सरकार की भागदारी के साथ-साथ ये RBI से कर्ज प्राप्त करते है |
- सहकारी व्यवस्था की ठीक करने के लिए वैद्यनाथन समिति का गठन किया गया | इस समिति के सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधार किये जा रहे है |

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

- भारत में सर्वप्रथम आर.जी.सरैया के नेतृत्व में गठित बैंकिंग आयोग ने 1972 में ग्रामीण बैंक की अवधारणा प्रस्तुत की | यद्यपि सरकार ने सरैया समिति की सिफारिश की पूरी तरह स्वीकार नही किया,किन्तु 2 अक्तूबर,1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की घोषणा की | 2 अक्टूबर,1975 को 5RRBS स्थापित किये गये |
- नरसिम्हन समिति के सुझावों के आधार पर 1975 में कृषि एवं ग्रामीण शाखा की आवश्यकता का पूरा करने के लिए इनका गठन किया गया | नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 पारित किया | 1987 तक सिसिक्म एवं गोवा को छोडकर कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई | 1987 के बाद किसी RRB की स्थापना नही की गई |
- 2012-13 के वजट में प्रस्तुत आकड़ो के अनुसार वर्तमान में 82 RRBS है जिसमें 81 ने कोर बैंकिंग अपना लिया है |
- कृषि एवं ग्रामीण शाखा की आवश्यकता के सदंर्भ में सर्वोच्च बैंक के रूप में NABARD(National Bank of Agriculture & Rural Development) की स्थापना की गई |
- इन 3 क्षेत्रों को 13 उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है |

- आधुनिक बैंकों की शुरुआत 1157 में इटली में बैंक ऑफ़ वेनिस की स्थापना से माना जाता है |
- भारत सरकार ने वित्तीय प्रणाली की विद्यमान संरचना तथा उसके विभिन्न अवयवों के आलोचनात्मक विवेचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गर्वनर एम.नरसिंहम की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय समिति का अगस्त,1991 में गठन किया | समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 नवम्बर,1991 को सरकार की सौपी |

## अनुसूचित बैंक :

- अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक को कहा जाता है जिनका RBI Act 1934 में उल्लेख ही तथा वो इससे जुडी शर्तो का पालन करते हो जैसे-बैंक की प्रदत पूँजी तथा संचित कोष 5 लाख से कम नही हो तथा अन्य शर्तो |
- अनुसूची-ii के बैंकों को बैंक दर पर RBI से कर्ज,Clearing House की सदस्यता तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त हो जाती है |
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 82 है | भारत में वर्तमान में कुल अनुसूचित बैंकों की संख्या 300 है,जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रके बैंक,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,अनुसूचित निजी क्षेत्र बैंक तथा शेष विदेशी बैंक शामिल है | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया को जारी रहने के कारण यह संख्या अंतिम नहीं है |

## गैर-अनुसूचित बैंक:

- ऐसे बैंक जो अनुसुचित नहीं है इन बैंकों को मौद्रिक नीति के तहत CRR को RBI के पास रखने की अनिवार्यता नहीं है | इनकी संख्या दिनों दिन कम हो रही है |
- गैर-अनुसूचित बैंक से आशय ऐसे बैंकों से है जिसे,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 को दूसरी अनुसूचित में सम्मिलित नहीं किया गया है | यह बैंक वैधानिक नकद आरक्षण आवश्यकताओं के अधीन है और इसको निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास न रखकर अपने पास रखने का अधिकार है |
- गैर-अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती प्रेषण तथा उधार लेने की सुविधा नहीं प्राप्त होती है |

### o RBI के नए दिशा-निर्देश:

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 अगस्त,2011 को देश में नए निजी बैंकों में लाइसेंस से संबधित बहु प्रतिक्षित दिशा-निर्देश का प्रारूप जारी |इन बैंकों में पहले पाँच साल तक विदेशी हिस्सेदारी 49% से अधिक नहीं हो सकेगी |
- नए दिशा-निर्देश के मुताबिक,नया निजी बैंक स्थापित करने के लिए अब कम्पनियों को कम से कम 500 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा |
- वर्तमान में नए निजी बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम 300 करोड़ रुपए की पूँजी की अनिवार्यता है |

## गोइपोरिया समिति सिफारिशों :

- बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए 1990 में RBI ने भारतीय स्टेट बैंक अध्यक्ष श्री एम.एन. गोइपोरिया का अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया | इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 5 दिसम्बर,1991 को प्रस्तुत कर दी गयी थी |

## निजी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के बैंक:

- इनका नियमन रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट,1934 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट,1949 तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 8% का पूँजी पर्याप्तता मानक रखना होगा |

## वर्मा समिति की सिफारिशे :

- कमजोर बैंकों की पुनर्सरचना हेतु सिफारिशे देने के लिए गठित एम.एस. वर्मा समिति ने अपनी सिफारिशे 4 अक्टूबर,1999 को सार्वजनिक कर दी गई समिति ने यूको बैंक,इंडियन बैंक एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के संचालनात्मक,संगठनत्मक,वित्तीय एवं व्यवस्था संबंधी पुनर्गठन के सुझाव रिपोर्ट में प्रस्तुत किए है |

## बैंकिंग लोकपाल योजना :

- बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए रिजर्व बैंक ने 14 जून,1955 से देश भर में बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम लागू कर दी है |

इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए 15 ग्राहक प्रहरी नियुक्त किए जा चुके है |

**देश का पहला मोबाइल बैंक :**

- देश का पहला बैंक खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इस चलते-फिरते बैंकों की स्थापना एक करोड़ रुपए की लागत से एक वैन में की गई जिस पर कुछ कर्मचारी तैनात है |

**कोच्चि में देश का पहला तैरता ATM:**

- स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 9 फरवरी,2004 को देश का पहला तैरता ATM स्थापित किया गया है यह ATM करेला शिंपिग and इनलैंड नेवीगेशन कॉपोरेशन के झंकार नामक स्टीमर में लगाया गया है (ATM-Automated Teller Machine )

**सर्वव्यापी बैंकिंग :**

- रिजर्व बैंक ने दिसम्बर,1997 में एस.एच.खान.तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया जिसका उद्देश्य मौद्रिक आर्थिकसुधारों की नई पृष्ठभूमि में विकास वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका,संरचना तथा परिचालकों की समीक्षाकरना तथा उनकी भूमिका तथा परिचालनों में सामंजस्य स्थापित करना था |
    - ऋण वसूली न्यायाधिकरण :
- बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऐसे ऋणों,जो वसूल नही हो पा रहे है की वसूली में तेजी लाने के लिए सरकार ने 8 शहरों
  कोलकाता,दिल्ली,जयपुर,अहमदाबाद,बंगलौर,चेन्नई, गुवाहाटी तथा पटना में ऋणवसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए है |
- एक अपीलीय न्यायाधिकरण मुंबई में भी कार्यरत है वर्ष 1994 में ऐसा पहला न्यायाधिकरण में स्थापित किया गया था |
- अगस्त,1925 में हिल्टन आयोग का गठन किया गया हिल्टन आयोग के गठन का उद्देश्य भारत में विनियम तथा मुद्रा प्रणाली की जाँच करके तथा इससे आवश्यक सुधार के लिए सुझाव देना था | हिल्टन आयोग द्वारा 1926 में देश में मुद्रा की प्रचलित प्रणाली के संदर्भ में असंतोष व्यक्त किया गया और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देश में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की अनुशंसा की |
- अगस्त 1947 में देश के विभाजन के बाद नये देश पाकिस्तान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून,1948 तक केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य किया |

**करेंसी नोटों का निर्गमन :**

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के अनुसार,रिजर्व बैंक को एक रुपए के सिक्के/नोटों एवं छोटे सिक्कों को छोडकर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है |
- ब्रिटिंश सरकार द्वारा 1882 में भारत में कागज की मुद्रा का आरंभ किया गया |
- भारत वर्ष 1947 में अतंर्राष्ट्रीयमुद्रा निधि का सदस्य बना तथा रुपए की विनियम दे आई.एम.एफ. मानकों के अनुसार तय की जाने लगी |
- दशमलव प्रणाली के तहत एक पैसे का सिक्का मार्च,1962 में जारी किया गया तथा प्रथम एक रुपए का सिक्का जुलाई,1962 में जारी किया गया |
- आर.बी.आई.द्वारा 3 अक्टूबर,1987 से महात्मा गाँधी के चित्र तथा अशोक स्तंभ प्रतीक से युक्त 500 रुपए वाली मुद्रा जारी की गयी |
- प्रत्येक बैंक नोट पर उसकी राशि 15 भाषाओं में लिखी जाती है |
- 15 अगस्त,1950 से देश में नए सिक्कों का चलन शुरू हुआ | सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार 1,000 रुपए तक मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते है |
- कागजी मुद्रा अधिनियम 1861 द्वारा सरकार को बैंक नोट जारी करने का अधिकार मिला जिससे प्राइवेट और प्रेसीडेंसी बैंकों का नोट जारी करने का अधिकार समाप्त हो गया |
- सरकार 1 अप्रैल,1935 यानि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य प्रारंभ के समय तक नोट जारी करने का अधिकार समाप्त हो गया |

- रिजर्व बैंक देश में मुद्रा प्रबंधन का कार्य संभालता है |
- रिजर्व बैंक ने 1938 में बैंक नोट जारी किए जिनमे पहले 5 रुपए के नोट पर जॉर्ज षष्ठम का चित्र बना हुआ था |
- रिजर्व बैंक सरकार की सिफारिश पर किसी भी मूल्य वर्ग के नोट जारी कर सकता है |
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार रिजर्व बैंक 10,000 रुपए मूल्यवर्ग तक बैंक नोट जारी कर सकता है |

## रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा०) लि०

- रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व ने 3 फरवरी,1955 को रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा०) लि. की स्थापना की गई है इसके तत्वाधान में मैसूर और शाहबनी में दो करेंसी प्रिंटिंग प्रेसो नए क्रमशः 1 जून,1996 और 11 दिसम्बर,1966 से नोट छपने का कार्य शुरू कर दिया |
- भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष भर मर चार बार मौद्रिक नीति की घोषणा करता है -जनवरी,अप्रैल,जुलाई,व अक्टूबर में |
- फरवरी,1974 तक रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओंर से भारत प्रतिरक्षा कानून के अंतर्गत विनियम नियन्त्रण करता था,लेकिन विदेशी विनियम नियमन अधिनियम,1947(FERA,1947) के बन जाने से इस संबंध में रिजर्व बैंक को स्वतंत्र उत्तरदायित्व मिल गया | इस अधिनियम क स्थान बाद में विदेशी विनियम नियमन अधिनियम,1973 ने ले लिया,जिसमे समय-समय पर संशोधन होते रहे | विदेशी विनियम नियमन अधिनियम के स्थान पर अब विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम लागू कर दिया गया है |

## भारत की टकसाल एवं छापेखाने

- इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस,नासिक रोड(महाराष्ट्र) इसकी दो इकाइयां है -
- **सेंटल स्टांप डिपो :**
    - यह माँग करने वाले निर्मित वस्तुओं का वितरण करता है |
- **करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड(महाराष्ट्र):**
    - 5,10,50,100,500,तथा 1000 रुपए के बैंक नोट छापने का कागज तैयार होता है |
- **सिक्यूरिटी पेपर मिल,होशंगाबाद (मध्यप्रदेश)**
    - अधिक मूल्य के नोट तथा नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर छापने का कागज तैयार होता है |
    - **बैंक नोट प्रेस.देवास(मध्यप्रदेश):**
- इसकी मुख्य प्रेस में 20,50,100, तथा 500 रुपए के नोट छापे जाते है |
- **सिक्यूरिटी प्रिटिंग प्रेस,हैदराबाद(आंध्रप्रदेश)**
    - केंद्रीय उत्पाद शुल्क के टिकट के आलावा अंतर्देशीय पत्र,पोस्टकार्ड तथा टिकट छपे लिफाफे भी छापे जाते है |
- **सरकारी टकसालें:**
    - मुंबई,कोलकाता,हैदराबाद तथा नोएडा में है जहाँ घरेलू आवश्यकता के लिए सिक्के ढालना,सोने और चांदी की परख करना और तमगों का उत्पादन होता है |

## साख नियन्त्रण की विधि :

- साख मुद्रा का नियन्त्रण भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य है | भारतीय रिजर्व बैंक साख नियन्त्रण के लिए परिणामत्मक तथा गुणात्मक का प्रयोग करता है |
- 12 जुलाई,1982 को कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हो जाने पर अब इसने रिजर्व बैंक से कृषि वित्त संबंधी कार्य ले लिया है |
- बैंकों के जमाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1962 में 'जमा बीमा निगम' की तथा बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए 1964 में 'यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया'की स्थापना की गई |
- रिजर्व बैंक ने संस्थागत औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक वित्त की व्यवस्था कर के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिकवित्त निगम और राज्य वित्त निगमों की स्थापना में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में हुई थी | जिसे 1976 में एक स्वायत्त संस्था बना दिया गया |

## बैंकिंग पर्यवेक्षण का बेसल समिति :

- बैंकिंग निरीक्षण पर बेसल समिति एक संस्थान है जिनकी स्थापना 10 देशों के केन्द्रीय बैंकों के गर्वनरों ने की थी | इसकी बैठक हर चार साल में स्विट्ज़रलैंड के बेसल में स्थित अंतर्राष्ट्रीय बैंक में होती है |

### बेसल-ii

- बेसल-ii बेसल संधि का दूसरा प्रारूप है जिसमे बेसल समिति द्वारा बैंकिंग कानून और नियमन के लिए सिफारिशें दी गयी है जून 2004 में अंतर्राष्ट्रीय मानक का निर्माण करना है जिसे बैंकिंग नियामक वित्तीय और परिचालन संबंधी खतरों से बैंकों को बचाने के लिए जरूरी पूँजी बैंकों के पास होने संबंधी नियमों का निर्माण करते समय प्रयोग कर सकें |

### बेसल-iii

- बेसल-iii बेसल संधि के नए सुधार है जिन पर कार्य चल रहा है सितम्बर,2010 में ही अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढाँचे को बेसल-iii के नाम से संबोधित करना शुरू किया | हालांकि,इस शब्द को पहली बार 2005 में प्रयोग किया गया था |
- 22 दिसंबर,1977 को राष्ट्रीय साख परिषद् की स्थापना की गई है | इसका उद्देश्य नए परिवर्तनों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर उच्च स्तरीय साख की आवश्यकताओं तथा प्राथमिकता का अध्ययन करना | उस समय राष्ट्रीय साख परिषद् के अध्यक्ष तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया गया तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर को उपाध्यक्ष बनाया गया |

## वित्तीय उत्तरदायित्व एवं विकास परिषद् :

- वर्ष 2008-09 के वित्तीय संकट में सम्पूर्ण विश्व में बैंकिग तथा वित्तीय बाजार की संरचना में आधारभूत परिवर्तन उत्पन्न किए है | वित्तीय स्थिरता बनाए एखने के लिए एक उचित प्रणाली को अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 2010-11 बजट में उच्च स्तर पर वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् गठित करने का निर्णय लिया था |

**अध्यक्ष : केन्द्रीय वित्त मंत्री**

सदस्य:1.RBI के गर्वनर

- 2.SEBI के अध्यक्ष
- 3.IRDA के अध्यक्ष
- 4.PFRDA के अध्यक्ष

उद्देश्य: वित्तीय स्थिरता

- वित्तीय क्षेत्र का विकास
- वित्तीय साक्षरता
- अंतर नियामक समन्वयक
- अर्थव्यवस्था की समविष्ट भावी निगरानी

## राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

- 12 जुलाई,1982 को केंद्र सरकार नेकृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक प्रथम राष्ट्रीय बैंक 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक' की स्थापना की | नाबार्ड की स्थापना मार्च 1979 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण विचार करने के लिए नियुक्त शिवरमन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की गई |
  - वित्तीय एवं संगठनत्मक प्रबंध :
- नाबार्ड की प्रारंभिक पूँजी 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी जिसमें केंद्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बराबर का योगदान किया जाना था | नाबार्ड की पूँजी 500 करोड़ रुपए तक बढ़ायी भी जा सकती है |
- नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है तथा देश भर में इसके 16 क्षेत्रीय कार्यालय है

नाबार्ड के कार्य :

- पूर्व में जो कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का कृषि ऋण विभाग तथा कृषि पुन: वित्त एवं विकास निगम कर रहा था | उसे पूरा करने के उद्देश्य के लिए नाबार्ड की स्थापना की स्थापना की गई |

## सहकारी क्षेत्र की प्रमुख समितियां

| समिति | कार्य | गठन |
|---|---|---|
| सर एडवर्ड लार्ड समिति | सहकारी साख संस्थाओं का विधान | 1901 |
| एडवर्ड मैक्लेगन समिति | सहकारी आंदोलन के मूल्याकन विकास आदि | 1914 |

| | | |
|---|---|---|
| | के संबंध में दिशा निर्देश | |
| आर.जी.सरैया समिति | सहकारिता नियोजन समिति | 1948 |
| एस.टी.राजा समिति | सहकारी कानून | 1956 |
| बैकुंडलाल मेहता समिति | सहकारी ऋण के विभिन्न पहलूओं पर विचार | 1959 |
| राम निवास मिर्धा समिति | सहकारी समिति | 1965 |
| के.एन.अर्द्धनारीश्वरन समिति | सहकारिता में स्वायत्तता | 1987 |
| चौधरी ब्रह्मा प्रकाश समिति | एक आर्दश राज्य सहकारी | 1990 |
| वैद्यनाथ समिति | कृषि सहकारी समितियाँ और कृषि ऋण ढ़ांचा | 2004 |

❁

## बैंकिंग सुधारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियां :

- ❁ नरसिम्हन समिति-1991 में गठित बैंकिंग क्षेत्र में चार स्तरीय ढ़ाँचे कि व्यवस्था व साख व लाइसेंसिंग की प्रणाली की समाप्ति तथा दुसरे सुधार में बड़े बैंकों को मिलाने पर बल और संकीर्ण बैंकिंग की धारणा को अपनाने पर बल दिया |
- ❁ खन्ना समिति-1998 में गठित और बैंकों का वित्तीय संस्थानों में सहयोग |
- ❁ सुब्बाराव समिति-2009 में गठित और मौद्रिक नीति में सुधार |
- ❁ दामोदरन समिति-2010 में गठित और उपभोक्ता सुविधाओं में सुधार |